



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2019/फाल्गुन 23, 1940
No. 192]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2019/PHALGUNA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019

सं. 13/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 219(अ).—जहां कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और सऊदी अरब (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "संतृप्त वसा अल्कोहल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 17, 2905 19 और 3823 70 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 14/51/2016-डीजीटीआर, दिनांक 23 अप्रैल, 2018, जिसे दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रश्नगत उत्पाद को विषयगत देशों में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया गया था और यहां इसके कारण इसकी भरमार हो गई है। इनमें से कुछ आयातों के कारण तो यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हो रही थी,

और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25 मई, 2018, जिसे सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 25 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था।

और जहां कि मैसर्स पीटी एनर्जी सेजाहेतेरा मास (प्रोड्यूसर), इंडोनेशिया और मैसर्स सिनारमस सेप्सा प्राईवेट लिमिटेड (एक्सपोर्ट/ट्रेडर), सिंगापुर ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार उस निर्यात के बारे में समीक्षा करने का अनुरोध किया है जो कि उनके द्वारा किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 'न्यू शीपर रिव्यू' अधिसूचना संख्या 7/38/2018-डीजीटीआर, दिनांक 15 जनवरी, 2019, जिसे 15 जनवरी, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उन सभी विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यातकों के अनंतिम आंकलन की सिफारिश की है जिसका निर्यात उपर्युक्त पार्टी ने किया है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसके द्वारा समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात एतद्वारा आदेश देती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा के परिणाम के आने तक विषयगत वस्तु, जब इनका मूलतः उत्पादन या निर्यात विषयगत देश में मैसर्स पीटी एनर्जी सेजाहेतेरा मास (प्रोड्यूसर), इंडोनेशिया के द्वारा और मैसर्स सिनारमस सेप्सा प्राईवेट लिमिटेड (एक्सपोर्ट/ट्रेडर), सिंगापुर के माध्यम से हुआ हो का तब तक अनंतिम आंकलन किया जाता रहेगा जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है।

2. यह अनंतिम आंकलन उस प्रतिभूति या गारंटी के अधीन होगा जिसे सीमा शुल्क का यथोचित अधिकारी यह समझे कि किसी प्रकार की कमी की स्थिति में भुगतान के लिए यह उपयुक्त है और यदि निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने के अधीन रहेगी।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा के पूरा होने के पश्चात प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की सिफारिश किए जाने पर आयातकर्ता उस प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा जो कि विषयगत वस्तुओं के सभी प्रकार के आयात, जब इनका मूलतः उत्पादन या निर्यात विषयगत देश में/से मैसर्स पीटी एनर्जी सेजाहेतेरा मास (प्रोड्यूसर), इंडोनेशिया के द्वारा और मैसर्स सिनारमस सेप्सा प्राईवेट लिमिटेड (एक्सपोर्ट/ट्रेडर), सिंगापुर के माध्यम से किया जा रहा हो और उनका भारत में आयात किया जा रहा हो। यह प्रतिपाटन शुल्क उक्त समीक्षा के प्रारंभ होने की तिथि से लागू होगा।

[फा. सं. 354/169/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2019

No. 13 /2019-Customs (ADD)

G.S.R. 219(E).—Whereas, in the matter of import of 'Saturated Fatty Alcohols' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 2905 17, 2905 19 and 3823 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority, *vide* its final findings notification No. 14/51/2016-DGAD, dated the 23rd April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd April, 2018, had come to the conclusion that the product under consideration exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. Some of the imports were also causing material injury to the domestic industry.

And Whereas, had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject countries;

And Whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/2018-Customs (ADD), dated the 25th May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 498(E) dated the 25th May, 2018;

And Whereas, M/s. PT. Energi Sejahtera Mas (Producer) Indonesia and through M/s. Sinarmas Cepsa Pte Ltd (Exporter/trader), Singapore have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, *vide* new shipper review notification No. 7/38/2018-DGTR, dated the 15th January 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th January 2019, has recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated party till the completion of the review by it;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when originating in or exported from the subject country by M/s. PT. Energi Sejahtera Mas (Producer) Indonesia and through M/s. Sinarmas Cepsa Pte Ltd (Exporter/trader), Singapore and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such security or guarantee as the proper officer of customs deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive antidumping duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said review by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of such anti-dumping duty recommended on review and imposed on all imports of subject goods when originating in or exported from the subject country by M/s. PT. Energi Sejahtera Mas (Producer) Indonesia and through M/s. Sinarmas Cepsa Pte Ltd (Exporter/trader), Singapore and imported into India, from the date of initiation of the said review.

[F. No. 354/169/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.